MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have said ...*(Interruptions)*... I can't expect the Minister to reply like that. ...*(Interruptions)*... Honourable Members, in the supplementary agenda which has been circulated, there is a Bill for consideration and passing. This Bill will be taken up later because there is a change. *(Interruptions)*

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: माननीय उपसभापति महोदय, मैं मांग नहीं कर रहा हूं, एक सूचना दे रहा हूं।

श्री उपसभापति: आप पत्र भी लिख सकते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: महोदय, यह आवश्यक है, होली के अवसर पर ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: ऐसे नहीं होगा।...(**व्यवधान**)...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: माननीय उपसभापति महोदय, होली के अवसर पर ऐसा हो रहा है कि सारी मेट्रो सिटीज ...(**व्यवधान**)... राजधानी प्रदेशों की है, वहां आरक्षण एक-एक, दो-दो महीने का नहीं होगा। आप नई रेल चलाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप पत्र लिखिए न।

डा॰ प्रभा ठाकुर: सर, एक मिनट मैं भी बोलना चाहती हूं।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You write a letter to get an assurance. ...*(Interruptions)*... You can meet him in Rail Bhavan. ...*(Interruptions)*...

डा॰ प्रभा ठाकुर: सर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं घोषणा की थी जन सभा में विश्व-स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने को अजमेर का ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: बैठिए।

डा॰ प्रभा ठाकुर: मैं बस वही याद दिला रही हूं, आश्वासन चाहती हूं...(**व्यवधान**)... वहां पूरी दुनिया के लोग आते हैं। इसीलिए मंत्री जी ने घोषणा की थी, बस उसी बारे में आप से आश्वासन चाहती हूं।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं...

श्री उपसभापति: तीनों पढ़ दीजिए।...(**व्यवधान**)...

GOVERNMENT BILLS

1. The Appropriation (Railways) Vote on Account Bill, 2008

2. The Appropriation (Railways) Bill, 2008

and

3. The Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 2008

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

"रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2008-2009 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

"रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2007-2008 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

"रेलों के प्रयोजनार्थ 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों के आधिक्य में व्यय की गई रकमों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Appropriation (Railways) Vote on Account Bill, 2008. The question is:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 2008-09 for the purposes of Railways, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *and* 3 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI LALU PRASAD: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Appropriation (Railways) Bill, 2008. The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services for the financial year 2007-08 for the purposes of Railways, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *and* 3 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI LALU PRASAD: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 2008. The question is:

"That the Bill to provide for authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services for the

purposes of Railways during the financial year ended on the 31st day of March, 2006 in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *and* 3 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill*

SHRI LALU PRASAD: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was added.

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Gireesh Kumar Sanghi. He is not here.

Demand for releasing the remaining amount of Post-Matric Scholarships to SC, ST and OBC students of Rajasthan

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान): माननीय उपसभापति महोदय, भारत सरकार की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राशि के भुगतान, पुनर्भरण का प्रकरण इस सदन में कई बार उठ चुका है। केन्द्र सरकार इस योजना में इतनी कम धनराशि देती है कि छात्रों को भुगतान नहीं किया जा सकता और पिछली बकाया आगे चलती जाती है। आलम यह है कि भारत सरकार द्वारा देय रुपए 124.83 करोड़ के विरूद्ध केवल रुपए 60.49 करोड़ ही दिया गया है और रुपए 64.34 करोड़ का अवशेष लंबित पड़ा है। भारत सरकार के पास कोई ठोस आधार या विश्वसनीय आंकड़ें नहीं होने पर भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को मान्य नहीं किया जाता फलस्वरूप देय राशि और प्राप्त राशि के बीच खाई बढ़ रही है।

महोदय, राज्य में साक्षरता की दर में वृद्धि के साथ उच्च शिक्षा में भी छात्रों की प्रवेश दर में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में 10 प्रतिशत से यह दर निरन्तर बढ़ रही है। व्यावसायिक शिक्षण की ओर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाती के छात्रों की बढ़ती हुई रूचि और उत्कृष्ट व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्ति की प्रवृत्ति से उक्त वर्गों के अधिक छात्र निजी क्षेत्र के संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं। इस तथ्य को भी भारत सरकार समझने और मानने को तैयार नहीं है। परिणामत: इन छात्रों की छात्रवृत्तियां हमेशा बकाया रहती हैं और बैक लॉग बढ़ता जा रहा है। समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्र वर्ग में आक्रोश है और यह कभी भी विस्फोट हो सकता है।

मैं मांग करता हूं कि बकाया राशि अविलंब रिलीज की जाए एवं ऐसी व्यवस्था की जाए कि मांग के अनुरूप धनराशि का आवंटन सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।

Poor state of higher education in the country

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, I rise to draw the attention of this House to the poor state of higher education in the country. Year after year, certain global organisations have been conducting surveys to rank the universities and higher education institutions worldwide. Of the 24 Central and 228 State universities, none O+ the Indian Universities has been ranked within the first hundred universities. To refute such rankings would be to refute the obvious as such studies are widely referred in the academic peerage. Such findings only corroborate the abysmally low rate of eight per cent enrolment in higher education.